

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3089
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओडिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

3089. श्री अनन्त नायक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम ओडिशा राज्य में और विशेषकर क्योझर जिले में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य में एनएचएम के अंतर्गत विशेषकर क्योझर जिले सहित ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में अवसंरचना अपर्याप्त है और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या ओडिशा राज्य में विशेषकर क्योझर जिले में कई अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, नर्सों और विशेषज्ञों सहित योग्य स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों की कमी है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों की भर्ती करने और मौजूदा पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य स्वास्थ्य के व्यापक सामाजिक निर्धारकों का समाधान करने के लिए प्रभावी अंतरक्षेत्रीय सम्मिलित कार्रवाई द्वारा समान, वहनीय और गुणवत्तायुक्त तथा जनता की आवश्यकताओं के प्रति जबाबदेह और अनुकूल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त कराना है। इसे ओडिशा सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। ओडिशा के स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति संबंधी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- ओडिशा ने देश में सबसे अधिक अंक की गिरावट दर्ज की, आईएमआर 2005 में 75 था जो 39 अंकों की गिरावट के साथ 2020 में 36 हो गया। (स्रोत: एसआरएस)
- राज्य ने कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को घटाकर 1.8 (भारत 2.0) करके जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों में एसडीजी लक्ष्य हासिल किया है। (स्रोत: एनएफएचएस)

- ओडिशा ने मातृ मृत्यु अनुपात में देश में दूसरी सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है, 2015-17 में 168 अंक था जो 49 अंक घटकर 2018-20 में 119 अंक हो गया है। (स्रोत: एसआरएस)
- राज्य ने 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण कवरेज में सभी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। (स्रोत: एनएफएचएस)
- टीबी के उन्मूलन की दिशा में अपने प्रयासों के लिए 2018 (14 वीं रैंक) में 60.5% स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर टीबी स्कोर के अनुसार राज्य की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है, जिसका 2023 में देश में दूसरा स्थान रहा।

(ख) से (ड): क्योँझर जिला सहित ओडिशा राज्य में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं तथा ओडिशा राज्य में डाक्टरों, नर्सों और विशेषज्ञों सहित स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों का ब्योरा निम्नलिखित यूआरएल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

ओडिशा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, क्योँझर जिले में डाक्टरों सहित प्रमुख स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ के रिक्त पदों की स्थिति का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन के सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों की भर्ती सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। इनका विवरण सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं :

<https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=45&lid=58>

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए निम्नलिखित निधियां आबंटित की हैं:

- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। ओडिशा राज्य को राज्य के

प्रस्ताव के अनुसार चार साल (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए 604 भवन रहित-एएएम (उप-केंद्र - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र), 140 शहरी-एएएम (यू-एचडब्ल्यूसी), 119 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 21 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज स्तर पर 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीवी) की स्थापना और सुदृढीकरण के लिए 1049.38 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- ओडिशा राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी- एक्सवी) के अंतर्गत, राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 1280 भवन-रहित उप स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (884 एसएचसी और 396 पीएचसी) और 90 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना और सुदृढीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में 1988.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और ओडिशा राज्य के लिए बहरामपुर, बुर्ला और कटक में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना', वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ओडिशा राज्य में बालासोर, बारीपदा, बोलनगीर, कोरापुट, पुरी, जाजपुर और कालाहांडी जिलों में 07 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी।

एनएचएम के अंतर्गत, डॉक्टरों की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच अंतराल को कम करने के लिए देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के दिशानिर्देश हैं:

- ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके लिए आवासीय क्वार्टर की व्यवस्था, ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करना आकर्षक समझें।

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव-पूर्व परीक्षण (एएनसी) जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और दाई (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए राज्यों को बातचीत द्वारा वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन लाना शामिल है।
- कठिन क्षेत्रों में सेवारत कार्मिकों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी एनएचएम के तहत शुरू किए गए हैं।
- एनएचएम के तहत विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों के बहु-कौशल होने का समर्थन किया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन करना एनआरएचएम के तहत एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

दिनांक 13.12.2024 को श्री अनंत नायक, माननीय सांसद द्वारा "ओडिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के संबंध में पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3089 के उत्तर के भाग (ख) से (ग) में उल्लिखित

अनुलग्नक।

क्योंझर जिले के प्रमुख स्वास्थ्य कर्मचारियों की रिक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	स्टाफ की श्रेणी	स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त पद
1.	डॉक्टर	672	313	359
2.	फार्मासिस्ट	136	100	36
3.	नर्सिंग स्टाफ	592	234	358
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ)	285	260	25
5.	लैब तकनीशियन	84	40	44
6.	रेडियोग्राफर	26	11	15
7.	एमपीएचडब्ल्यू (महिला)	562	461	101
8.	एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष)	245	230	15
